

जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और डीए रीसेट पर टिकी कर्मचारियों की नजर

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होने जा रहा है और ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद तेज हो गई है.



बढ़ती महंगाई और पिछले एक दशक से न्यूनतम वेतन में कोई बदलाव न होने के कारण कर्मचारी संगठनों की निगाहें नए वेतन आयोग पर टिकी हैं. 7वें वेतन आयोग ने 2016 में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया था, ग्रेड पे खत्म किया गया था और नई पे मैट्रिक्स लाई गई थी. उस समय न्यूनतम बेसिक पे सीधे 18,000 रुपये तय किया गया था. हालांकि, अब लगभग 10 साल बाद महंगाई भत्ता (डीए) 58प्रतिशत तक पहुंच चुका है, लेकिन बेसिक वेतन जस का तस है. यही वजह है कि 8वें वेतन

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है. न्यूनतम बेसिक पे में बड़ा इजाफा हो सकता है. डीए को दोबारा रीसेट किया जा सकता है. पेंशनर्स को भी सीधा लाभ मिल सकता है. कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद. यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक तय होता है, तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये या उससे ऊपर जा सकता है. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बड़ा उछाल आएगा. कर्मचारी संगठन इसे महंगाई और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से जरूरी सुधार बता रहे हैं.

आयोग से उच्च फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग तेज हो गई है.

6वें वेतन आयोग के अंतिम दौर में डीए 119प्रतिशत तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए 7वें वेतन आयोग में शून्य से शुरू किया गया था. अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है. लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा सैलरी डीए और एचआरए जोड़ने के बाद 33,000-34,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, लेकिन महंगाई के मुकाबले यह अपर्याप्त मानी जा रही है.

एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से निकाले 74,822 करोड़ रुपये



मुंबई, 28 दिसंबर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल 26 दिसंबर तक भारतीय पूंजी बाजार से 74,822 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी है. शुद्ध निकासी का मतलब है कि उन्होंने जितना पैसा बाजार में लगाया है उससे 74,822 करोड़ रुपये ज्यादा निकाले हैं.

अकेले दिसंबर में अबतक 29,571 करोड़ रुपये की निकासी की गयी है जो जनवरी के बाद सबसे अधिक है. साल के 12 में से आठ महीने एफपीआई बिकवाल रहे हैं जबकि शेष चार महीने वे शुद्ध रूप से लिवाब रहें हैं. सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, पूरे साल के दौरान एफपीआई ने शुद्ध रूप से 1,52,227 करोड़ रुपये की इकटिरी बेची. वहीं, उन्होंने जमकर डेट में खरीदारी की.

उन्होंने 72,893 रुपये के डेट की शुद्ध खरीद की. म्यूचुअल फंड में उनका शुद्ध निवेश 10,877 करोड़ रुपये रहा. हाइब्रिड उपकरणों में भी उन्होंने 1,442 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. दिसंबर में एफपीआई ने 14,734 करोड़ रुपये की इकटिरी की शुद्ध बिकवाली की. महीने के दौरान डेट, हाइब्रिड उपकरणों और म्यूचुअल फंड में भी उनका निवेश नकारात्मक रहा.

आर्थिक आंकड़ों से तय होगी बाजार की चाल

मुंबई, 28 दिसंबर. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर रहेगी. अगले सप्ताह सोमवार को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किये जायेंगे.

इसके बाद 02 जनवरी को औद्योगिक क्षेत्र के खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के आंकड़े जारी होंगे और सप्ताह के दौरान ही वाहनों की बिक्री के आंकड़े भी आयेंगे. बीते सप्ताह गुरुवार को क्रिसमस के अवकाश के कारण बाजार में चार दिन ही कारोबार हुआ. बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक संसेक्स में 112.09 अंक (0.13 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त रही और यह



सीमा शुल्क विभाग ने सहयोग और विश्वास पर दिया जोर

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. सीमा शुल्क विभाग के दिल्ली जोन ने कहा है कि निर्यात-आयात कारोबार में लगे समुदाय के साथ विश्वास, प्रणाली को दृढ़ता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग चाहता है.

वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा ईदिया गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दिल्ली जोन के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में सीमा शुल्क मंजूरी

सुविधा समिति (सीसीएफसी) की बैठक में विभाग के अधिकारियों ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की. बैठक कहा गया कि क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है. ये मूल्य के केवल सीमा शुल्क के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्वास निर्माण और यह सुनिश्चित करने का आधार हैं. विश्वास के आधार पर ही हितधारक प्रशासन के साथ खुलकर संवाद करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं.

व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक

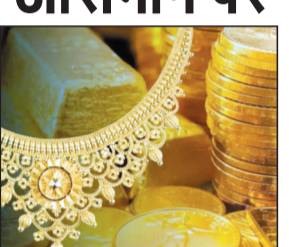
भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार में सुगमता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए सीमा शुल्क विभाग, सहयोगी एजेंसियों, संरक्षकों और व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है. मुताबिक निर्णय पारदर्शिता, प्रक्रियाओं में सुगमता और संवाद एवं समस्या-समाधान के लिए खुली नीति को अपनाकर, दिल्ली सीमा शुल्क विभाग विश्वास, दक्षता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है. यह बैठक आयात और आयात कारोबार में सुगमता और भरोसा बनाये रखने और बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है. इस बैठक में एफएसएसएआई, प्लॉट कार्टरटाइन और इमा कंट्रोलर सहित सहयोगी सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ कस्टम्स ब्रोकर, एसायमें और जीजिईपीसी जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड! कीमतें आसमान पर

1.41 लाख रुपए उछला सोना

2.35 लाख रुपए पहुंची चांदी

नई दिल्ली 28 दिसंबर. आज सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं. 24 कैरेट सोना लगभग 1,41,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,35,000 प्रति किलो के पार पहुंच गई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त के कारण निवेशक उत्सुक हैं और बाजार में हल्की घबराहट भी देखी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस उछाल का मुख्य कारण वैश्विक बाजार के रुझान और डॉलर की मजबूती है.



अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े संकेत भी सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं. मुख्य बातें-ऐतिहासिक ऊंचाई-सोना और चांदी अब तक के उच्चतम स्तर पर बड़ी उछाल चांदी में इस साल 150प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी, सोने में भी भारी उछाल. शहरों में असर-लखनऊ, कानपुर, पटना और भीपाल में भी कीमतें आसमान छू रही हैं.

मुद्रा लोन से 52 करोड़ लोगों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के जरूरत मंद लोगों को लोन की सुविधा दी जाती है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना और छोटे कारोबार को शुरू व विस्तार में मदद देना है. इसके लिए बैंक शाखाओं, एनबीएफसी और एमएफआई के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. अब तक इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को मजबूती मिली है और लाखों लोग स्वरोजगार की ओर बढ़े हैं. 2025 में योजना का फोकस लोन सीमा बढ़ाने, नई श्रेणियां जोड़ने और महिला व वंचित वर्गों को सशक्त करने पर है. एस्वीआई

राउंडअप 2025

धीरूभाई की जयंती पर छात्रवृत्ति योजना की घोषणा

देश के 5100 होनहार छात्रों को रिलायंस फाउंडेशन का सहारा



स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी की 93वीं जयंती पर इस साल की छात्रवृत्ति के निर्णयों की शनिवार को घोषणा की. प्रतिष्ठान अब तक 33437 युवाओं को छात्रवृत्ति दे चुका है. रिलायंस फाउंडेशन ने

सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 35,439 करोड़ रुपये घटा

मुंबई 28 दिसंबर. संसेक्स में तेजी के बावजूद पिछले सप्ताह बीएसई की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 35,439 करोड़ रुपये घट गया जबकि अन्य तीन का 22,113 करोड़ रुपये बढ़ा. बाजार पूंजीकरण के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे अधिक 12,692 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया. विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकेन 8,255 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का 5,102 करोड़ रुपये घट गया.

चावल और खाद्य तेलों में साप्ताहिक तेजी, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 28 दिसंबर. घरेलू थोक जिनस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये. वहीं, गेहूं और चीनी के भाव लगभग स्थिर रहे. खाद्य तेलों में तेजी रही जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. घरेलू थोक जिनस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत दो रुपये की मामूली बढ़त के साथ सप्ताहांत पर 3,829 रुपये प्रति क्विंटल रही. गेहूं 2,857 रुपये प्रति क्विंटल पर कमोबेश अपरिवर्तित रहा. आटा छह रुपये महंगा हुआ

यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट के क्या मायने?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी पर अब पार्टी में ही घमासान शुरू गया है यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन को अग्रगण्यसहीना मान कर कार्रवाई की चेतावनी दी है, इसके बाद से विपक्षी दलों सपा हो या कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट के महत्व को समझते हुए खुलकर ऑफर देने शुरू कर दिए हैं.

उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें भी शक नहीं की ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में करीब 10 से 11 फीसदी की भागीदारी है ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को अपने पाली में लाने का लालच सभी सियासी दलों को रहता है खासतौर से मायावती के

अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने ही भाजपा विधायकों को यह हिदायत जारी की गई तो उसके बाद तो जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया. दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने-अपने स्तर पर ब्राह्मण विधायकों को अपने पक्ष में आने के लिए ऑफर जारी कर दिया.

ब्राह्मण विधायक निराशा क्यों

भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कल 52 ब्राह्मण विधायकों में से 46 ब्राह्मण विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए बैठक में ब्राह्मण के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की थी. बैठक में शामिल विधायक शलभ माणि त्रिपाठी के अनुसार बैठक में यह माना गया था कि उत्तर प्रदेश का 90 फीसदी ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट करता है फिर भी उन्हें सरकार में वह भागीदारी नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी और संगठन में भी उनका वर्चस्व कम हो रहा है. इस बैठक को मानसून सत्र में हुए छठी विधायकों की बैठक के जवाब से जोड़कर देखा गया हालांकि बैठक में शामिल होने वाले ब्राह्मण विधायक इससे इनकार कर रहे हैं.

समाचार विशेष



डिट्टी स्पीकर ने छोड़ी कुर्सी

मोदी के गृह राज्य में मचा सियासी हड़कंप

अहमदाबाद. पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई अहीर भारवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद सुबे में सियासी हलचल बढ़ गई है. जानकारी के मुताबिक, भरवाड़ ने नाफेड समेत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कार्यों में समय देने और अपने अन्य दायित्वों को निभाने के कारण यह निर्णय लिया है. आपको बता दें कि मध्य गुजरात में जेठाभाई अहीर भारवाड़ एक प्रमुख सहकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं और सहकारी क्षेत्र में उनका विशेष दबदबा रहा है. भरवाड़

गुजरात में बढ़ गई राजनैतिक हलचल

इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि जेठाभाई अहीर भारवाड़ से इस्तीफा इस वजह से दिलाया गया है, जिससे किसी और नेता को यह पद सौंपा जा सके. डिट्टी स्पीकर के अलावा इस्तीफे से राज्य में राजनैतिक हलचल जरूर बढ़ गई है. सवाल यह भी उठ रहा है कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है? हालांकि, इस फैसले की पीछे की असली वजह क्या है? इसका ठीक-ठीक बयान कर पाना मुश्किल है. फिलहाल सियासत में कुछ भी अधिक समय तक छुकर नहीं रह सकता. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इस्तीफे का क्या कुछ कारण सामने आता है.

श्रापित हरिनापुर से तीसरी बार नहीं लड़ूंगा चुनाव

किस बात से डर रहे योगी के मंत्री



श्रापित मानी जाती रही है, और यही कारण है कि यहां से राजनीति करने वाले नेताओं को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए. दोबारा जीतकर राजनीतिक मिथक तोड़ा- खटीक ने हाल ही में हस्तिनापुर से दोबारा विधायक बनकर एक बड़ा राजनीतिक मिथक तोड़ा है. कहा जाता रहा है कि इस सीट से कोई भी व्यक्ति दोबारा विधायक नहीं बन पाता, लेकिन खटीक ने लगातार जीत दर्ज कर इस धारणा को गलत साबित किया. हालांकि, उन्होंने

विशेष डीके शिवकुमार ने खरगे से की मुलाकात, फिर कुर्सी पर चर्चा?

कर्नाटक का कलह पहुंचा दिल्ली!

बेंगलुरु. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मङ्गलार्जुन खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को तुरंत हवा दे दी. बैठक के समय को लेकर सवाल उठने लगे. हालांकि शिवकुमार ने बातचीत के तुरंत बाद पत्रकारों से कहा कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई. पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई. उनके मुताबिक, बातचीत पूरी तरह से केंद्र द्वारा मनरगे के नाम को बदलने के कदम और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर केंद्रित थी. उपमुख्यमंत्री ने कहा, किसी अन्य मुद्दे को उठाने का कोई कारण नहीं था. ना ही मैंने ऐसा किया और न ही करूंगा. वर्तमान में ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है. मुख्यमंत्री सिद्धार्थमा और मैंने दोनों ने स्पष्ट किया है कि हम आलाकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. वहीं शिवकुमार ने खुद को पदों के दावेदार के रूप में नहीं बल्कि एक

